सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-30 अंक-17 7 सितम्बर, 2015 मुख्य संपादक कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती कुल पृष्ठ 8 मूल्य : 2 रुपये

कॉमरेड माओ त्से-तुंग लाल सलाम

26 सितम्बर 1893 9 सितम्बर 1976

''पूंजीवादी देशों में सर्वहारा वर्ग की पार्टी का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह दीर्घकालीन कानूनी संघर्ष के जरिये मजदूरों को शिक्षित करे तथा अपनी शक्ति का संचय करे और पूंजीवाद का तख्ता अन्तिम रूप से उखाड़ फेंकने के लिए तैयारी करे। उक्त देशों में मसला यह है कि दीर्घकाल तक कानूनी संघर्ष चलाया जाए, पार्लियामेंट को एक मंच के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, आर्थिक और राजनैतिक हड़तालें की जाएं, ट्रेड यूनियनों को संगठित किया जाए और मजदूरों को शिक्षित किया जाए। ...लेकिन यह बगावत और युद्ध तब तक नहीं छेड़ना चाहिए जब तक पूंजीपति वर्ग वास्तव में असहाय नहीं हो जाता, जब तक सर्वहारा वर्ग का बहुसंख्यक जन-समुदाय सशस्त्र विद्रोह करने और युद्ध चलाने के लिए संकल्पबद्ध नहीं हो जाता, तथा जब तक किसान जन-समुदाय स्वेच्छा से सर्वहारा वर्ग को मदद नहीं देता।''**– माओ त्से-तुंग**(युद्ध व रणनीति की समस्याएं)

2 सितम्बर की देशव्यापी अभूतपूर्व हड़ताल के लिए केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने दी मजदूरों को बधाई

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर 2 सितम्बर को लाखों मजदूर-कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी अभूतपूर्व हड़ताल हुई। ऐसा समर्थन पहले कभी नहीं मिला था। देश में यह अब तक की सबसे बड़ी हड़ताल रही। इसका आह्वान 10 केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ऑल इण्डिया यूटीयूसी, सीआईटीयू, एटक, यूटीयूसी, टीयूसीसी, इंटक, एचएमएस, एआईसीसीटीयू, सेवा और एलपीएफ ने किया था। हजारों स्थानीय यूनियनों, असम्बद्ध एसोसियेशनों और फैडरेशनों ने इसका समर्थन किया। ट्रेड यूनियनों की व्यापक एकता ने ही यह कमाल कर दिखाया। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में इसका असर देखने को मिला। हड़ताल को लोगों का चौतरफा समर्थन मिला। ट्रेड यूनियनों के 12-सूत्री मांगपत्र पर सरकार के नकारात्मक रवेये के खिलाफ हड़ताल का आह्वान किया गया था। इनमें प्रमुख मांग थी कारपोरेट घरानों के हक में श्रम कानूनों में संशोधनों के लिए भारत सरकार द्वारा उठाये जा रहे हमलावर कदम।

हम बहादुर मजदूरों का अभिनन्दन करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इससे सबक लेगी और मेहनतकश जनता की दु:ख-तकलीफों को कम करने के लिए कदम उठायेगी। मांगों के ठोस हल की खातिर केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों से सरकार को पुन: वार्ता शुरू करनी चाहिए वरना संघर्ष को और तेज किया जायेगा। सरकार की मजदूर-विरोधी नीतियों के खिलाफ मेहनतकश जनता में बढ़ते असंतोष की वजह से ही हड़ताल इतनी व्यापक और अभूतपूर्व रही। खाद्य पदार्थों के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी और भारी छंटनी व इंफोरमेलाइजेशन का सबब बनी अर्थव्यवस्था की मंदी को रोकने में सरकार की नाकामी के खिलाफ भी यह प्रतिवाद था।

परिवहन, कोयला, उर्जा, बैंक, राज्य सरकार के कर्मचारी, बीमा, पोर्ट एण्ड डॉक, टेलिकॉम और ऑटोमोबाइल उद्योगों में हड़ताल अभूतपूर्व रही। हड़ताल को शानदार ढंग से सफल बनाने के लिए हजारों हजार मजदूर सड़कों पर उतर आये। दिल्ली में भी हड़ताल का अच्छा-खासा असर रहा। पश्चिम बंगाल में इस हड़ताल के लिए ट्रेड यूनियनों द्वारा किये जा रहे शान्तिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई और दंगाइयों द्वारा की गई ज्यादतियों की केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने कड़ी निन्दा की यह सरकार समर्थित आतंकवाद है। हमारा विश्वास है कि पश्चिम बंगाल के ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं पर की गई ज्यादतियों के खिलाफ देश के सभी सही सोच रखने वाले लोग एकजुट होकर प्रतिवाद करेंगे। सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के बावजूद ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं ने आज अडिग रह कर हड़ताल को सफल बनाया। हम उन्हें बधाई देते हैं।

(शेष पृष्ठ 3 पर)

कॉमरेड शिवदास घोष के चिंतन को आत्मसात करें, साम्यवाद कायम करने के महान संघर्ष में खुद को लगा दें

–कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती

(एसयूसीआई(सी) के पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती ने यह भाषण 8 अगस्त को बंगलोर में कॉमरेड शिवदास घोष 39वें स्मृति दिवस पर आयोजित सभा में दिया था।)

कॉमरेड सभाध्यक्ष और दोस्तो,

मानव समाज में मृत्यु कोई नई बात नहीं है। समाज की शुरूआत से ही जन्म और मृत्यु होती आई हैं। निस्संदेह हर मौत ही समाज में ख़ला पैदा करती है, लेकिन नये जन्म इस ख़ला को भर देते हैं। लेकिन कोई-कोई ऐसी मौत होती है जो एक ऐसी ख़ला पैदा कर देती है जिसे भरने में युग लग जाते हैं। ऐसी ही एक मौत 5 अगस्त, 1976 को हुई थी जब सर्वहारा के महान नेता, महान मार्क्सवादी चिन्तनकार, हमारी पार्टी के नेता, शिक्षक कॉमरेड शिवदास घोष का देहांत हो गया था। उनकी मौत असामयिक थी। लेकिन इतने थोड़े समय में ही उन्होंने एक तरफ सर्वहारा की क्रान्तिकारी पार्टी सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर आफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का निर्माण किया और दूसरी तरफ क्रान्तिकारियों द्वारा किसी संघर्ष को संचालित किये जाने के लिए सम्पूर्ण चिन्तन और दिशा निर्देश प्रदान किया। उन्होंने स्वयं क्रान्ति के बारे में जहां समग्र ज्ञान प्रदान किया वहीं साथ ही साथ अंतराष्ट्रीय साम्यवादी आन्दोलन के सामने उभर कर आये तमाम सवालों का भी जवाब दिया। इसलिए उनका चिन्तन महान था जो ज्ञान और जीवन के तमाम क्षेत्रों को समोये हुए था। एक चर्चा में सभी क्षेत्रों को समेटना असम्भव है। सचमुच ही सभी सवालों पर एक चर्चा में बोलना असम्भव है। इसलिए उनके मुख्य विचार जो क्रान्ति के सवाल, खास कर आज भारत की क्रान्ति के विशेष स्वरूप पर केन्द्रित हैं, उनको आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा।

क्रान्ति क्या है?

असल में क्रान्ति क्या है? क्रान्ति के सवाल पर लोगों में विभिन्न तरह की धारणाएं हैं। जब लोग जीवन में बहुत कठिनाइयों का, संकट का सामना करते हैं, जिन समस्याओं का समाधान आसानी से नहीं हो सकता, तब वे कहते हैं कि क्रान्ति ही एकमात्र समाधान है; हमें क्रान्ति चाहिए। क्या वे समझते हैं कि क्रान्ति क्या है? निश्चित ही नहीं। उनमें से कुछ लोगों ने हो सकता है समझ लिया हो लेकिन उनमें से ज्यादातर नहीं समझते हैं कि क्रान्ति का सही-सही मायने क्या है। इसके अलावा, लोगों का एक तबका क्रान्ति के ही खिलाफ है। वे समझते हैं कि क्रान्ति अराजकता है, इसका मतलब व्यक्तिगत हत्याएं करना है। क्या ये लोग क्रान्ति को समझते हैं? ये भी नहीं समझते हैं। लेकिन क्रान्ति को समझे बिना निश्चित ही हम इसे सफल नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें क्रान्ति सफल करनी होगी, इसलिए कॉमरेडों को, खास कर हाल ही में पार्टी में शामिल हुए युवा होनहार कॉमरेडों को इसे अच्छी तरह समझना होगा कि हम किस लिए संघर्ष कर रहे हैं? ठीक-ठीक, सही

बंगलोर में सभा को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती

रूप में क्रान्ति का क्या मायने है? आज भारतीय क्रान्ति का चरित्र क्या है? अत: मैं कॉमरेड शिवदास घोष की इस शिक्षा पर अपनी बात रखूंगा।

पूरे ब्रह्माण्ड में हम क्या पाते हैं? – चाहे प्रकृति में, समाज या जीवन में हो, हर चीज बदल रही है और हर पल चीजें निरंतर गति में हैं। लेकिन यह बदलाव जो हर किसी चीज में हो रहा है, दो रास्ते अपनाता है– एक है परिमाणगत परिवर्तन, धीमे-धीमें होने वाला परिवर्तन, क्रमविकासात्मक परिवर्तन और दूसरा है गुणात्मक परिवर्तन, हटात् परिवर्तन, अप्रत्याशित परिवर्तन, पूरी की पूरी चीज का एक नई चीज में परिवर्तन जिसे मार्क्सवाद की भाषा में हम कहते हैं परिमाणगत परिवर्तन से गुणगत परिवर्तन का होना। यह गुणात्मक परिवर्तन जो हर पहलू में पूरी की

(शेष पृष्ठ 2 पर)

कॉ. कृष्ण चक्रवर्ती का भाषण ..

(पृष्ठ 1 का शेष)

पूरी चीज को नई चीज बना देता है इसे हम क्रान्ति कहते हैं। अत:, क्रान्ति किसी की पसन्द या नापसंद पर निर्भर नहीं है, क्रान्ति हर रोज हर समय पूरे ब्रह्माण्ड में, प्रकृति में, समाज में, जीवन में, मानव चिन्तन में भी हो रही है।

आम तौर पर लोग सोचते हैं कि क्रान्ति सिर्फ मानव समाज में ही होती है। हाँ, निश्चित ही क्रान्ति मानव समाज में होती है लेकिन यह सिर्फ मानव समाज में ही नहीं होती है, बल्कि प्रकृति में भी क्रान्ति होती है, मानव चिन्तन में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन होता है। अगर हम बारीकी से देखें तो बहुत ही साधारण तरीके से हम समझ सकते हैं, अगर उपजाऊ जमीन में एक गेहूँ का दाना बो दिया जाए, अगर इसे आवश्यक पानी, हवा, सूर्य की किरणें मिलें तो हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद इससे अंकुर फूटता है और कुछ और दिनों के बाद हम देखेंगे कि गेहूँ का दाना पूरी तरह खत्म हो गया और एक पौधा उग आया है। यह नई अवस्था यानी जब पुराना पूरी तरह नया बन गया है, पौधे जैसे एक नये गुण लेकर आ गया है जो बीज के गुणों से भिन्न है, इस खास क्षण को हम क्रान्तिकारी परिवर्तन कहते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि पूरे वस्तुजगत में, यहाँ तक कि कठोरतम पत्थरों में भी परिवर्तन हो रहा है। हर चीज में परिवर्तन हो रहा है; परिवर्तन वस्तु और वस्तुजगत के अस्तित्व का ढंग है। यह दो रास्ते अपनाता है–परिमाणगत से गुणगत परिवर्तन। वह पौधा एक दिन में बीज से नहीं आया, बल्कि धीरे-धीरे परिमाणात्मक रूप से बदलते-बदलते, अचानक एक दिन यह परिवर्तन हो गया। क्रान्ति यही है। सामाजिक जीवन में भी क्रान्ति यही रास्ता अपनाती है जैसा कि प्रकृति में होता है, हालाँकि हूबहू वही नहीं। दो परिवर्तन समरूप नहीं हो सकते हैं। विज्ञान में यह बात हम जानते हैं। समाज में वह क्रान्तिकारी रास्ता क्या है इसे हमें समझना चाहिए।

समाज में क्रान्ति की धारा

जैसे हम प्रकृति में देखते हैं कि परिवर्तन स्वाभाविक रूप में सामान्य तरीके से होता है। अगर कोई विशेष व्यवधान न हो–जैसे बीज को हवा, पानी या रोशनी नहीं मिली, कभी-कभार ऐसे किसी व्यवधान के सिवा परिमाणगत परिवर्तन से गुणगत परिवर्तन के लिए कोई व्यवधान नहीं है। हालाँकि समाज में यह मूल रूप से यही रास्ता अपनाता है लेकिन समाज में परिवर्तन अपने आप नहीं हो जाता है, खास कर वर्ग-विभाजित समाज में, जहाँ दो वर्ग हैं–एक शोषक वर्ग जो समाज पर शासन करता है और दूसरा शोषित वर्ग जो शासित, शोषित, दमित-उत्पीड़ित है–वहाँ क्रान्ति अपने आप नहीं हो सकती है। सामाजिक क्रान्ति में स्वचालन नहीं है। यहाँ पूरी तरह एक नये कारक की जरूरत है जो मानव चेतना है। सचेत मानव संघर्ष के बिना क्रान्ति नहीं होगी। लेनिन ने कहा है, ''क्रान्तिकारी सिद्धांत और एक क्रान्तिकारी पार्टी के बिना क्रान्ति नहीं होगी।''

ऐसा क्यों? हम सर्वहारा क्रान्ति के लिए अनुकूल परिवेश तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समाज में हम ही तो इकलौती ताकत नहीं हैं। शासक वर्ग–सत्ता पर काबिज पूँजीपति वर्ग, टाटा, बिडला, गोयन्का, अंबानी, अडानी, यानी शोषक वर्ग, जहाँ राज्य रूपी मशीन –जिसका मायने है फौज, पुलिस, अफसरशाही, न्याय व्यवस्था, इन चारों का एक साथ इस्तेमाल करते हुए, इस राजसत्ता का इस्तेमाल करते हुए क्रान्ति का विरोध करता है। वे क्रान्ति के रास्ते में बाधा डालते हैं। जब समाज में क्रान्ति का प्रतिरोध बढ़ता है तो इसे रोकने के लिए, इसे तोड़ने के लिए, परास्त करने के लिए हमें शोषित जनता के एक क्रान्तिकारी संगठन की जरूरत पड़ती है जो शासक वर्ग के हमलों का मुकाबला कर सके, जो न केवल उनकी पुलिस बल्कि फौज को भी परास्त कर सके। ऐसी शक्ति का जब समाज में सचेत रूप से निर्माण किया जाता है केवल तभी सामाजिक क्रान्ति हो सकती है। अत: जो लोग क्रान्ति को अराजकता और अन्य काल्पनिक रूप में सोचते हैं यह वैसी नहीं है, यह सचेत संगठित सर्वहारा क्रान्ति है, लोगों का सशस्त्र अभ्युत्थान है, नक्सलवादियों की तरह यहाँ-वहाँ छिटपुट लोगों को मारना नहीं है बल्कि संगठित अभ्युत्थान है। यह है क्रान्ति। अत:, दो ताकतों–समाज में दो वर्गों, शासक वर्ग और शासित वर्ग, शोषकों और शोषितों के बीच यह संघर्ष है। इसलिए सचेत प्रयास के बिना क्रान्ति नहीं हो सकती है।

हिंसा और क्रान्ति

बहुत से लोग कहते हैं कि आप हिंसा भड़काते हैं। लोग नहीं बल्कि पूँजीपति वर्ग और उसके गुर्गे यह प्रचारित करते हैं कि क्रान्ति अराजकता है और यह हिंसा पैदा करती है। लेकिन मजदूर वर्ग कभी हिंसा पैदा नहीं करता है, वे इसे नहीं चाहते हैं। तब हथियार बंद क्रान्ति की बात हम क्यों करते हैं? क्योंकि एक वर्ग-विभाजित समाज जैसा कि हमारा है, इसमें जब मजदूर वर्ग सचेत रूप से खुद को संगठित करता है, आन्दोलन गठित करता है तो उसे कौन दबाता है? भारी शस्त्रों से लैस पुलिस। जब पुलिस ऐसे किसी आन्दोलनों को दबा नहीं पाती है, तब फौज बुलाई जाती है। पूँजीवादी समाज में सर्वहारा और अन्य उत्पीड़ित जन के क्रान्तिकारी आन्दोलन का दमन करने के लिए ही फौज बनाई और रखी जाती है। शासक वर्ग और इसके टुकड़खोर चाकर हमें बताते हैं कि हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए, खुद को विदेशी हमलों से बचाने के लिए यह फौज जरूरी है और जनसेवा के लिए, बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में लोगों को बचाने और उनकी मदद करने के लिए इसकी जरूरत है। यह लोगों को भ्रमित करता है लेकिन आप समझ लें कि फौज को अंतत: कान्तिकारी आन्दोलन को दबाने और क्रान्तिकारी ताकतों को तहस-नहस करने के लिए ही सहेज कर रखा जाता है। अगर मजदूर और अन्य शोषित तबके सचेत रूप से संगठित होते हैं, अगर वे सोचें कि वे सत्ता दखल करने के लिए तैयार हैं जो समाज के लिए जरूरी है, तो मजदूरों को शासक वर्ग की फौज का सामना करना होगा, इसलिए हिंसा होती है। शासक पूँजीपति वर्ग है जो हिंसा पैदा करता है और फिर मजदूर वर्ग और अन्य शोषित जनता पर आरोप लगाता है। इसलिए जब तक शासक-शोषक वर्ग अपने सशस्त्र बलों को बरकरार रखते हैं तब तक हिंसा होगी ही। क्या फ्रांसीसी क्रान्ति में हिंसा नहीं हुई थी? फ्रांसीसी क्रान्ति को किसने संगठित किया था? क्या कम्युनिस्टों ने यह क्रान्ति की थी? कम्युनिस्ट तो तब पैदा भी नहीं हुए थे! यह पूँजीपति वर्ग ही था जो आज मजदूर वर्ग पर हिंसा का आरोप लगाता है। यही थे जिन्होंने उस क्रान्ति को सरअंजाम दिया था और फ्रांसीसी क्रान्ति में, खास कर हत्याओं पर हत्याओं के बाद, रोब्सपियरे जिन्होंने गिलोतीन का आविष्कार किया था, खुद गिलोतीन कर दिये गये थे। क्या यह बुरा था? यह कोई बुरा नहीं था। तब क्या मनुष्य की हत्या करना अच्छा काम है? बात यह नहीं है। क्रान्ति में लोग मारे जायेंगे क्योंकि शासकों की भाड़े की फौज जब गोली चलायेगी बहुत सारे बेगुनाह मरेंगे। लेकिन अगर यह समाज को बदलती है, अगर यह एक ऊंची, उन्नत सभ्यता का निर्माण करती है, एक महान, उन्नत और उदात्त समाज बनाती है जिसमें मानव पुराने बंधनों से मुक्त कर दिया गया हो, तब तो यह स्वागत योग्य है। वह हिंसा तब महान है। क्रान्ति के लिए अगर खून बहाना जरूरी है तो बहाना होगा। हम खून-खराबा नहीं चाहते लेकिन यह मजदूर वर्ग पर थोप दिया जायेगा जब मजदूर वर्ग सचेत रूप से संगठित होकर फौज का सामना करता है तो यह गृह युद्ध में तब्दील हो जाता है और यही क्रान्ति है।

इसलिए, हमें देखने को मिलता है कि जब तक शासक पूँजीपति वर्ग सत्ता में रहता है, तब तक क्रान्ति हिंसक ही होगी। इस वजह से नहीं कि हम चाहते हैं, बल्कि इसकी वजह यह है कि वे इसे मजदूर वर्ग पर थोप देते हैं। तब क्या सभी क्रान्तियाँ हिंसक होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं! जब आदिम जंगली समाज धीरे-धीरे गुणात्मक रूप से बर्बर युग में तब्दील हुआ तो यह एक क्रान्ति थी लेकिन शांतिपूर्ण थी। क्योंकि खुद को बचाने के लिए क्रान्तिकारी आन्दोलन को तबाह करने के लिए कोई दमनकारी वर्ग सत्ता में नहीं था। इसी तरह जब मजदूर वर्ग सत्ता पर काबिज हो जायेगा –एक सर्वहारा वर्गीय राजसत्ता कायम हो जायेगी, तब सर्वहारा का एकनायकत्व होगा। लेकिन जब समाज समाजवाद से साम्यवाद में पदार्पण करेगा तब इसे रोकने के लिए बल प्रयोग नहीं होगा, शस्त्रों का प्रयोग नहीं होगा। बल्कि इसके विपरीतं शासक वर्ग यानी सर्वहारा वर्ग ही खुद क्रान्ति चाहेगा। इसलिए यह शांतिपूर्ण होगी। तब हिंसक क्रान्ति हम कहाँ देखते हैं? हम इसे वर्ग-विभाजित समाज में देखते हैं, खास कर जहाँ शासक पूँजीपति वर्ग, शोषणकारी वर्ग सत्ता में होता है –चाहे वह सामंतवाद हो या गुलामतंत्र हो या पूँजीवाद। वहाँ क्रान्ति ऐसा एक रूप धारण करती है। इसलिए सर्वहारा क्रान्ति में सर्वहारा वर्ग की सचेत भूमिका एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है, सिर्फ सचेत सर्वहारा की ही नहीं बल्कि संगठित सर्वहारा वर्ग की भूमिका। केवल सचेत संगठित सर्वहारा वर्ग ही शस्त्र उठा सकता है और समाजवाद यानी सर्वहारा वर्ग का शासन कायम करने के लिए पूँजीपति वर्ग को सत्ता से उखाड़ फेंक सकता है। यह एक महान क्रान्ति है और यह एक बहुत ऊंची, उन्नत नई सभ्यता को जन्म देगी जो उन तमाम समस्याओं का समाधान करेगी जिनसे आज हम दो-चार हैं–यह एक महान सामाजिक आन्दोलन है।

भारतीय क्रान्ति का स्तर

अगला बिन्दु है हमारी क्रान्ति यानी भारतीय क्रान्ति का चरित्र क्या है? जिसे कॉमरेड शिवदास घोष ने सारगर्भित विश्लेषण करते हुए बताया कि यह एक पूँजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रान्ति होगी। इसका मतलब क्या है? आइये बहुत बारीकी से इसकी जाँच करें कि इस तरह की क्रान्ति क्या होती है? पहले हमें यह समझना होगा कि भारत एक पूँजीवादी देश है। भारत एक पूँजीवादी देश है कि नहीं इस बारे में तथाकथित कम्युनिस्टों के बीच भ्रान्तियाँ हैं। इस देश में एक भी तथाकथित कम्युनिस्ट पार्टी यह स्वीकार नहीं करती है कि भारत एक पूँजीवादी देश है। वे यह कहाँ स्वीकार करेंगी कि भारत केवल एक पूँजीवादी देश ही नहीं है बल्कि एक बहुत शक्तिशाली पूँजीवादी देश है जहाँ राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग, एकाधिकारी घराने साम्राज्यवादी बन गये हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारतीय साम्राज्यवादी खुद दूसरे गरीब देशों में पूँजी निर्यात करते हैं और उनके प्राकृतिक संसाधनों और सस्ती श्रम शक्ति का शोषण-दोहन करते हैं। आजादी से पहले अंग्रेज हमारे देश में पूँजी निर्यात करते थे, उन्होंने सीधा सैनिक शासन कायम किया हुआ था और उसके जरिये भारतीय बाजार का शोषण-दोहन करते थे। भारतीय पूँजीपति आज वही भूमिका दूसरे देशों में निभा रहे हैं हालाँकि यह किसी देश को सैन्य तौर पर नियंत्रित नहीं करता है। कोई भी साम्राज्यवादी देश अब किसी भी अन्य देश को सैन्य तौर पर नियंत्रित नहीं कर सकता है चाहे वह इंग्लैण्ड हो या फ्रांस या जर्मनी हो या अमेरिका। लेकिन वित्तीय पूँजी निर्यात करके वहाँ की सस्ती श्रम शक्ति और सस्ते खनिज पदार्थों का शोषण-दोहन करते हैं। भारत भी यही कर रहा है। इसलिए भारत न केवल एक पूँजीवादी देश है बल्कि एक साम्राज्यवादी ताकत–दक्षिण एशियाई क्षेत्र में एक मिनी सुपर पावर है। इसलिए हमें पहले यह समझना चाहिए कि भारत एक पूँजीवादी देश है। तब एक पूँजीवादी देश में क्रान्ति का चरित्र क्या हो सकता है इसे समझना चाहिए।

लेनिन ने दिखाया है कि सामाजिक क्रान्ति के संदर्भ में क्रान्ति का मुख्य सवाल राजसत्ता का सवाल है। शोषितों द्वारा राजसत्ता पर कब्जा किया जाना क्रान्ति है। पुरानी राज्य मशीनरी को ध्वस्त किये बिना और नई राजसत्ता कायम किये बिना सर्वहारा वर्ग क्रान्ति नहीं कर सकता है। उन्हें राजसत्ता पर कब्जा करना होगा, उन्हें पूँजीवादी राज्य मशीनरी को ध्वस्त करना होगा, इसे तोड़ देना होगा और सर्वहारा वर्ग की नई राजसत्ता कायम करनी होगी। ऐसा क्यों? अतीत में कायम हुई तमाम राजसत्ताएं –चाहे गुलाम-मालिक राजसत्ता रही हो, या सामंती राजसत्ता या पूँजीवादी राजसत्ता–ये सभी शोषणमूलक राजसत्ताएं थी। उन राजसत्ताओं को सुधार कर या बेहतर बना कर सर्वहारा वर्ग अपनी खुद की राजसत्ता के तौर पर काम में नहीं ले सकता। मजदूर वर्ग को इसकी जगह एक नई राजसत्ता कायम करनी होगी जो समाज को शोषण से मुक्त करेगी, जो अतीत की शोषणमूलक राजसत्ता से पूरी तरह और गुणात्मक रूप से भिन्न होगी। यह राजसत्ता सुनिश्चित करेगी कि मानव द्वारा मानव का शोषण नहीं किया जाता है, कि तमाम मजदूर ही उत्पादन

(शेष पृष्ठ 4 पर)

2 सितम्बर की देशव्यापी अभूतपूर्व हड़ताल के लिए केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने दी मजदूरों को बधाई

(पृष्ठ 1 का शेष)

देश के विभिन्न हिस्सों में लाठीचार्ज भी किया गया। मजदूरों को पुलिस द्वारा हड़काये जाने और गिरफ्तारी के मामले भी हुए हैं। कुछ राज्यों में एस्मा लगाये जाने के बावजूद इस हड़ताल को शानदार रूप से सफल बनाने के लिए अविचलित रहते हुए मजदूर आगे बढ़े। केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने अंधाधुंध पुलिस कार्रवाई की निन्दा की।

केरल, आसाम, गोआ, तेलगााना, पाण्डिचेरी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड आदि राज्यों में पूर्ण हड़ताल रही, लगभग सभी सरकारी क्षेत्रों और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र भी हड़ताल पर रह। इनमें से अनेक राज्यों में व्यापारियों ने भी अपना कारोबार और दुकानें बंद कर दी थी जिसके चलते बंद जैसी स्थिति बन गई थी। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडू, दिल्ली और मेघालय आदि राज्यों में हड़ताल का व्यापक असर रहा जहां कुछ क्षेत्रों में सौ प्रतिशत हड़ताल रही।

2 सितम्बर की देशव्यापी हड़ताल के दिन सड़कों पर उतरे श्रमिक, छात्र, आमजन

गुना

आईटीओ, दिल्ली

जयपुर

रोहतक

पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला

भिवानी

दुर्ग

सूरत

घाटशिला

जौनपुर

मुरादाबाद

वाराणसी

कॉ. कृष्ण चक्रवर्ती का भाषण ..

(पृष्ठ 2 का शेष)

के साधनों के मालिक हैं। जबकि पूँजीवाद में कुछेक व्यक्ति ही उत्पादन के साधनों के मालिक हैं। पूँजीपति फैक्टरियों, मिलों, उद्योगों, बड़े-बड़े फार्मों में मजदूरों का शोषण करते हैं। वे मजदूर की श्रम शक्ति खरीदते हैं और उसे उत्पादन में लगाते हैं। इसके ऐवज में मजदूरों को वे बेहद कम मजूरी देते हैं और बाकी को मुनाफे के रूप में हड़प लेते हैं। समाजवाद में शोषण नहीं रहेगा। यह एक नया समाज है जहाँ उत्पादन के तमाम साधन समाज के अधीन रहेंगे और राजसत्ता सर्वहारा वर्ग द्वारा संचालित होगी, जहाँ उत्पादन मुनाफा कमाने के लिए नहीं होगा बल्कि समाज की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए होगा। ऐसा एक समाज निश्चित ही भिन्न और ऊंचे दर्जे का होगा। अगर हम समझते हैं कि हमारा समाज शोषणमूलक है तब हम अपनी क्रान्ति के ठोस स्वरूप को समझ सकेंगे।

भारतीय क्रान्ति पूँजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रान्ति क्यों है?

लेनिन ने दिखाया कि समाज में क्रान्ति का सवाल राजसत्ता का सवाल है जैसाकि अभी हमने चर्चा की। स्टालिन ने इसकी विस्तार से व्याख्या की और दिखाया कि क्रान्ति में हमें पहले यह देखना है कि कौन सा वर्ग या वर्गों का समूह राजसत्ता में है, कौन सा वर्ग क्रान्तिकारी वर्ग है जो दूसरे वर्गों के साथ मिल कर क्रान्ति को नेतृत्व देगा। क्रान्ति का यही मुख्य सवाल है। शासक वर्ग और शासित वर्ग की पहचान करनी होगी। शासितों में से कौन सबसे ज्यादा क्रान्तिकारी है जो क्रान्ति को नेतृत्व देगा इसे समझना है। एक देश विशेष की क्रान्ति को समझने के लिए इसकी सही समझदारी होनी चाहिए। हमारे देश में 1948 में जब पार्टी स्थापित की गई तब कॉमरेड शिवदास घोष ने दिखाया था कि 1947 तक यहाँ ब्रिटिश साम्राज्यवादी ताकतों के साथ भारतीय सामंती भूस्वामियों और मैसूर रियासत, निजाम हैदराबाद, पटियाला आदि रियासतों (प्रिंसली स्टेट्स) के गठजोड़ का शासन था। ऐसी 500 से ज्यादा रियासतें ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ गठजोड़ में थी। इसलिए सत्तासीन वर्ग का मतलब सामंतवाद के साथ मिला हुआ विदेशी साम्राज्यवाद था। तब कौन सी ताकतें थीं जिन्हें क्रान्ति का नेतृत्व करना था? अब मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा। नये कॉमरेडों को ये मुश्किल लग सकता है लेकिन यह महत्वपूर्ण है और मैं व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, अगर समझने में दिक्कत हो तो वे बाद में राज्य नेतृत्व से समझ लें। टाटा, बिड़ला, गोयन्का जो फिलहाल सत्ता में हैं, उस समय नहीं थे। उस समय स्थानीय सामंती भूस्वामियों के साथ ब्रिटिश साम्राज्यवादी सत्ता में थे। इसलिए, वे भारतीय बाजार पर नियंत्रण चाहते थे, वे राजसत्ता पर नियंत्रण चाहते थे। विशाल बाजार के साथ भारत एक विशाल देश है, इसलिए उन्होंने भारतीय बाजार के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। कांग्रेस राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग की प्रतिनिधि संस्था थी। लेकिन साम्राज्यवाद पहले ही आ चुका था, पूँजीवाद जब साम्राज्यवाद की अवस्था में पहुँच कर और भी प्रतिक्रियावादी व मरणासन्न हो जाता है यानी पूँजीपति वर्ग अब और क्रान्ति का नेतृत्व नहीं कर सकता है। पूँजीपति वर्ग अन्तर्राष्ट्रीय तौर पर बहुत प्रतिक्रियावादी हो गया है। इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग का हिस्सा होने के नाते उपनिवेशों के पूँजीपति वर्ग, खास कर हमारे देश में उस हद तक पूँजीपति वर्ग की प्रगतिशील भूमिका थी जिस हद तक वह विदेशी साम्राज्यवाद और सामंतवाद के खिलाफ लड़ा था लेकिन वह सर्वहारा क्रान्ति से बुरी तरह भयभीत था। तब तक सर्वहारा वर्ग न केवल अस्तित्व में आ चुका था बल्कि खुद को एक वर्ग के रूप में संगठित भी कर लिया था, खास कर रूस में सर्वहारा क्रान्ति पहले ही हो चुकी थी। इसलिए पूँजीपति वर्ग सर्वहारा वर्ग की क्रान्ति से जबरदस्त डरा हुआ था। इसलिए वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और उनके साथ समझौता भी किया। उन्होंने कोई सांस्कृतिक आन्दोलन नहीं चलाया। इसलिए सामंतवाद और सामंती अवशेषों, सामंती संस्कृति, आदतों, दस्तूरों, रश्मो-रिवाजों को उन्होंने भारतीय जनता में बरकरार रहने दिया। अगर सामंती दस्तूरों, आदतों और संस्कृति के खिलाफ वे लड़े होते तो इसने एक नया संघर्ष छेड़ दिया होता जिसमें सर्वहारा वर्ग अगली कतार में आ गया होता। यह थी भारतीय राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग की भूमिका। जबकि बहुत सारे क्रान्तिकारी जैसे सुभाष चन्द्र बोस, भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, मास्टरदा और अन्य कई मध्यम वर्ग से आये थे, उन्होंने कांग्रेस की लाइन के खिलाफ संघर्ष की गैर-समझौतावादी धारा का अनुसरण किया। इसलिए ये समझौतावादी और गैर-समझौतावादी दोनों ही ताकतें हमारे आजादी आन्दोलन में थी। हालाँकि दुर्भाग्यवश आजादी आन्दोलन पर क्रान्तिकारी ताकतों का नेतृत्व कायम नहीं हो सका। आजादी आन्दोलन का नेतृत्व अंतत: भारतीय पूँजीपति वर्ग ने, खास कर कांग्रेस के माध्यम से हथ्यिा लिया था।

दूसरे विश्वयुद्ध के बाद जब स्थिति ऐसी हो गई कि स्टालिन के महान नेतृत्व में समाजवाद की विजय सुनिश्चित हो गई, जब सारा पूर्वी यूरोप समाजवादी बन गया और चीन भी स्वतंत्र हो गया, ऐसी स्थिति में जब दुनिया में समाजवादी खेमा वजूद में आ गया तो ब्रिटिश साम्राज्यवादी भयाक्रांत हो गये। इसलिए उन्होंने सत्ता भारतीय राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग को सौंप दी जो कम से कम उनके सौतेले भाई थे ताकि सत्ता कहीं सर्वहारा वर्ग के हाथों में न चली जाए। अगर वे कुछ साल और इस देश में रहते तो कुछ साल और शासन कर सकते थे। लेकिन उन्हें डर था कि देश में एक क्रान्तिकारी आन्दोलन पनप रहा था, अगर यह आन्दोलन आजादी आन्दोलन का नेतृत्व करने लगा तो न केवल अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ दिया जायेगा बल्कि भारतीय पूँजीपतियों को भी कभी सत्ता हथियाने नहीं दी जायेगी। भारतीय सर्वहारा वर्ग तब अन्य समाजवादी देशों के साथ मिल जाएगा, इसीलिए अंग्रेजों ने चालाकी से सत्ता भारतीय पूँजीपति वर्ग को सौंप दी। इसलिए आजादी सत्ता का हस्तांतरण था, सत्ता का एक शांतिपूर्ण हस्तांतरण। इसलिए बहुत से लोग यह नहीं समझते हैं कि वास्तव में ही यह एक क्रान्ति थी। जब सामंती भूस्वामी वर्ग के साथ-साथ ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के शासन का अंत हो गया राजसत्ता चली गई और दूसरे वर्ग यानी पूँजीपति वर्ग ने सत्ता पर कब्जा कर लिया जैसा कि भारत में हुआ—यह एक क्रान्ति थी। इसलिए जैसाकि कॉमरेड शिवदास घोष ने बताया कि भारतीय क्रान्ति अधकचरे और आधे-अधूरे ढंग से हुई। उसके बाद से भारत पूरी तरह एक पूँजीवादी राजसत्ता है जिसका शासन राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग के हाथ में है। इस तथ्य को ही अविभाजित सीपीआई और बाद में विभाजित सीपीआई, सीपीआई(एम), नक्सलवादी, कोई भी नहीं समझ पायी। लेनिन की सीखों के हवाले से कॉमरेड शिवदास घोष ने दिखाया कि रूस भी बहुत हद तक ब्रिटिश-शासित भारत जैसा ही था। उद्योग बहुत हद तक विकसित नहीं हुए थे। कृषि कार्य ही मुख्य गतिविधियाँ थीं। जब फरवरी क्रान्ति सम्पन्न हो गई तो सभी ने सोचा कि वे पूँजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रान्ति नहीं कर सकते हैं। लेनिन ने बताया कि जैसे ही फरवरी क्रान्ति के जरिये राजसत्ता जारशाही शासकों से रूसी पूँजीपति वर्ग के हाथ में चली गई, उस हद तक बुर्जुआ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न हुई और रूस पूँजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रान्ति के स्तर में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने कहा कि राजसत्ता का एक वर्ग के हाथों से दूसरे वर्ग के हाथों में हस्तांतरण ऐतिहासिक तौर से, राजनैतिक तौर से, वैज्ञानिक तौर से एक क्रान्ति है। लेनिन की इस शिक्षा को लेते हुए कॉमरेड शिवदास घोष ने भारतीय परिस्थिति का अध्ययन किया और इस नतीजे पर पहुँचे कि जब भारत की राजसत्ता किसी भी तरीके से समझौते के जरिये ब्रिटिश साम्राजयवादियों-सामंती भूस्वामियों के हाथों से भारतीय पूँजीपति वर्ग को हस्तांतरित हो गई उस हद तक हमारे देश में बुर्जुआ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न हो गई भले ही अधकचरे और आधे-अधूरे ढंग से हुई। अब भारतीय राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग राजसत्ता पर काबिज है। कौन से क्रान्तिकारी वर्ग हैं जो इस राजसत्ता को हासिल करेंगे? खेतिहर मजदूर, औद्योगिक मजदूर से मिल कर बना भारतीय सर्वहारा वर्ग सबसे क्रान्तिकारी वर्ग है। इस वर्ग के नेतृत्व के तहत ही जनता का अर्ध-सर्वहारा तबका यानी गरीब किसान, बढ़ई दस्तकार आदि दक्ष मजदूर, मध्यम वर्ग को क्रान्ति के पक्ष में लाकर पूँजीपति वर्ग को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। इसी वजह से हमारी क्रान्ति पूरी तरह पूँजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रान्ति है। इसका उद्देश्य पूँजीपति वर्ग को सत्ता से उखाड़ फेंकना और सर्वहारा वर्ग का राज कायम करना है।

क्रान्ति कब होती है?

यहाँ एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात आपको समझनी है। एक देश में जहाँ मौजूदा व्यवस्था—सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक —मरणासन्न, पुरानी और प्रतिक्रियावादी नहीं हो गई हो तो चाहे आप कितना ही संघर्ष करो और क्रान्ति लाने की बात करो, लेकिन वहाँ क्रान्ति नहीं कर सकते, इसके ऐसा हुए बिना कहीं भी कोई क्रान्ति नहीं हो सकती। लेकिन जब यह व्यवस्था पुरानी, मरणासन्न और प्रतिक्रियावादी हो गई और नई ताकत जो पुरानी को उखाड़ फेंक कर नई सभ्यता कायम करेगी, वह जब सत्ता दखल करने के लिए परिपक्व हो गई हो केवल तभी क्रान्ति होती है। मार्क्सवाद का अनुसरण करते हुए लेनिन ने दिखाया था कि पिछली सदी की शुरूआत में जब एक समय सामंतवाद के मुकाबले पूँजीवाद प्रगतिशील था तब यह नया जीवन, नया समाज लाया था; संस्कृति, विज्ञान और तकनीकी का द्वार खोल दिया था और इसी के चलते उद्योग-धंधे, मिलें और फैक्टरियाँ विकसित हुई थी। समाज आगे बढ़ा था लेकिन पूँजीवाद की उच्चतम अवस्था यानी साम्राज्यवाद में पहुँच कर पूँजीवाद पुराना, मरणासन्न और प्रतिक्रियावादी बन गया है। यह केवल जीवन की समस्याएं, जीवन का संकट पैदा कर सकता है, किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। हम यह देख भी रहे हैं कि संकट पर संकट आ रहा है। शिक्षा, संस्कृति, नीति-नैतिकता का क्षेत्र, आर्थिक-सामाजिक कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ संकट न हो। इस संकट के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या कोई एक विशेष सरकार-व्यक्ति-मनमोहन सिंह या नरेन्द्र मोदी? कोई व्यक्ति या राजनैतिक पार्टी इस संकट के लिए जिम्मेदार नहीं है; यह व्यवस्था ही है जो प्रतिक्रियावादी, पुरानी और मरणासन्न हो गई है। वे जो अब इस पुरानी, प्रतिक्रियावादी और मरणासन्न व्यवस्था, जनविरोधी व्यवस्था की ही ताबेदारी में लगे हुए हैं। वे प्रतिक्रियावादी हो गये हैं। कांग्रेस, बीजेपी और अनेक अन्य पार्टियों में से ज्यादातर पार्टियाँ पूँजीवाद की ही सेवा करती हैं। जब मजदूर वर्ग न केवल अस्तित्व में आ गया है बल्कि परिपक्व भी हो गया है और सचेत व संगठित हो गया है, वह पुराने वर्ग को सत्ता से उखाड़ फेंक कर नया समाज स्थापित करनने में सक्षम है। लिहाजा ऐसा नहीं है कि हम क्रान्ति की बात कर रहे हैं इसीलिए क्रान्ति हो जायेगी। क्रान्ति आसन्न है; यह उस दिन का इंतजार कर रही है जब मजदूर वर्ग सचेत रूप से क्रान्ति के लिए आगे आयेगा। समाज हाहाकार कर रहा है, रो रहा है न केवल हमारे देश में बल्कि सभी जगह। तमाम विकसित पूँजीवादी देशों की तरफ देखिये—सभी जगह संकट है। ग्रीस में क्या हो रहा है? कल्पना से परे संकट ने उस देश को जकड़ लिया है। माता-पिता अपने बच्चों को बेच रहे हैं। वे उनका पालन-पोषण नहीं कर सकते हैं। कुछ पैसों के लिए वे बच्चों को बेच रहे हैं। क्या स्थिति है माताओं को अपने बच्चे बेचने पड़ रहे हैं। स्पेन, फ्रांस, इंग्लैण्ड, अमेरिका, पूरे अरब जगत को देखिये—तूफान की तरह कैसा एक आन्दोलन फूट पड़ा—हर जगह वही संकट व्याप्त है। ऐसा क्यों? पूँजीवादी शोषण-उत्पीड़न की वजह से—इसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। ऐसे बड़े शक्तिशाली आन्दोलन जबरदस्त सम्भावनाएं लिये हुए हो रहे हैं, फिर भी क्रान्ति क्यों नहीं हो रही है? ये आन्दोलन क्यों पीछे हट गये? अब लेनिन की शिक्षाएं उचित, अमूल्य और सही साबित हुई कि क्रान्तिकारी सिद्धांत और एक क्रान्तिकारी पार्टी के बिना क्रान्ति नहीं होगी। इसलिए भारत में वही प्रतिक्रियावादी ताकत सत्ता में है—पूँजीपति वर्ग, वही प्रतिक्रियावादी व्यवस्था—पूँजीवाद अब शासन कर रहा है। तब हमारी क्रान्ति में दुश्मन कौन है? दुश्मन है टाटा, बिड़ला, गोयन्का, अम्बानी, अडानी—राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग—यह एक समांगी वर्ग, पूँजीपति वर्ग है। यहाँ क्रान्ति की ताकतें कौन हैं? क्रान्ति की मित्र शक्तियाँ

(शेष पृष्ठ 6 पर)

मीडिया से परोसी जा रही अश्लीलता और महिलाओं पर बढ़ते अपराध के खिलाफ

दिल्ली में आयोजित किया गया महिला सम्मेलन

दिल्ली : प्रचार माध्यमों द्वारा फैलाई जा रही अश्लीलता और महिलाओं व बच्चियों पर बढ़ते जा रहे अपराधों के खिलाफ अखिल भारतीय महिला सांस्कृतिक संगठन (एआईएमएसएस) की ओर से 23 अगस्त को आईटीओ स्थित गालिब ऑडिटोरियम में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। सभ्य समाज पर इस कलंक के विरोध में आवाज बुलंद करने के दृढ़ संकल्प के साथ आयी महिलाओं से खचाखच भरे सभागार में हुए इस सम्मेलन में समाज के हर क्षेत्र से महिलाएं शरीक हुई जिनमें शिक्षिका, अध्यापिका, वकील और लेखक भी शामिल थी। सम्मेलन की अध्यक्षता एडवोकेट दीपिका जैन ने की। सम्मेलन में सुप्रसिद्ध हिन्दी लेखिका चन्द्रकांता और पोर्नोग्रफी के विरुद्ध जनहित याचिका डालने वाले एडवोकेट विजय तंजवानी वक्ता रहे। एआईएमएसएस की अध्यक्ष सुश्री छाया मुखर्जी, एआईएमएसएस की महासचिव डा. एच जी जयालक्ष्मी और एआईएमएसएस कीदिल्ली राज्य सचिव सुश्री रितु कौशिक ने महिलाओं का आह्वान किया कि वे अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें। वक्ताओं ने दिखाया कि किस तरह टीवी, प्रिंट व इलैक्ट्रोनिक मीडिया, इंटरनेट की साइटों एवं अन्य जनसंचार माध्यमों द्वारा महिलाओं को मात्र खरीद-बेच की एक वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इससे लोगों में हानिकारक मानसिकता का संचार हो रहा है। इस पर चिंता व्यक्त की गई कि कैसे ये संचार माध्यम नवयुवको की मानसिकता पर कुप्रभाव डालते हैं जिसके कारण महिलाओं और बच्चियों पर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा शराब के ठेकों और दुकानों का तेजी से फैलाव और इससे भी बढ़ कर सरकारों की इन सब बुरे रुझानों के प्रति उदासीनता, खास कर इन अपराधों को बढ़ावा दे रही है।

दिल्ली के गालिब सभागार में महिला सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए डा. एच जी जयालक्ष्मी

वक्ताओं ने लोगों, खास कर महिलाओं को अश्लीलता और महिलाओं व बच्चियों पर बढ़ते जा रहे अपराधों के खिलाफ एक जोरदार समझौताहीन आन्दोलन खड़ा करने के लिए आवाज दी। सम्मेलन में ये मांगे रखी गई : साइबर कानून को सख्ती से लागू किया जाये, टीवी को प्रेस काउन्सिल ऑफ इण्डिया के तहत लाया जाए, एडवरटाइजमेंट स्टैडर्डस ऑफ इण्डिया(एआईसीआई) को सशक्त बनाया जाए ताकि वह सिर्फ निर्देश देने तक ही सीमित न रहे बल्कि उन्हें लागू भी कर पाए और पोर्नोग्राफिक विषयवस्तु के उत्पादन एवं प्रसारण को समाप्त करने के लिए सख्त कानून बनाया जाए।

किसान-खेतमजदूरों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर एआईकेकेएमएस ने प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन

भिवानी : 1 सितम्बर को यहाँ ऑल इण्डिया कृषक खेत मजदूर संगठन(ऑल इण्डिया के.के.एम.एस.) की ओर से उपायुक्त भिवानी कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। संगठन का एक प्रतिनिधिमण्डल उपायुक्त, भिवानी से मिला और उनकी मार्फत मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार के नाम एक ज्ञापन भेजा गया।

ज्ञापन में किसानों की सभी फसलों के लाभकारी दाम देने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत खर्च से 50 प्रतिशत ज्यादा हो, कृषि सब्सिडी बढ़ा कर खाद, बीजों, कीटनाशकों, औजारों, डीजल, बिजली के दाम आधे करने, खेती के लिए 12 घण्टे बिजली सप्लाई देने, गरीब किसानों के कर्जे खत्म करने, बैंकों द्वारा कर्जवान किसानों की जमीन की कुर्की न की जाने, खेत-मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाने, उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, किसानों की फसल को हुए नुकसान का पर्याप्त मुआवजा देने, फसल खराब होने के सदमे से या आत्महत्या करके मरने वाले किसान परिवारों को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने और प्रभावित किसान-खेतमजदूरों के कृषि ऋण माफ करने, आवारा पशुओं पर नियंत्रण करने और खनन पर लगाई गई रोक हटाने की मांग की गई। इसके अलावा कृषि भूमि अधिग्रहण पर मुकम्मल रोक लगाने, हर खेत को पानी और हर हाथ को रोजगार देने, सबको निशुल्क शिक्षा व इलाज का अधिकार देने, मनरेगा मजदूरों को साल में 365 दिन काम और कम से कम 300 रु. मजदूरी देने, यूरिया खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सभी गरीबों को सस्ता राशन देने, सभी किसान-खेतमजदूरों व दस्तकारों को 3000 रुपये प्रति महीना बुढ़ापा पैंशन देने, सभी गरीबों के मुफ्त आवासीय प्लाट देने और 5-5 लाख रुपये की ग्रांट देने की भी मांग की गई।

भिवानी में प्रदर्शन करते हुए किसान-खेतमजदूर

ज्ञापन देने गये प्रतिनिधिमण्डल में संगठन के राज्य सचिव कॉ. विजय कुमार, जिला सचिव रोहताश सेनी, फूलसिंह, सुखबीर, मनोहर लाल, उदयवीर, मनीराम, मास्टर राजकुमार आदि शामिल थे।

इससे पहले 20 अगस्त को तोशाम ब्लॉक, 24 अगस्त को कैरू ब्लॉक और 28 अगस्त को बवानी खेड़ा तहसील स्तरीय प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार को मांगों के ज्ञापन अधिकारियों की मार्फत सौंपे गये।

ज्वलंत समस्याओं के खिलाफ किसान-खेत मजदूरों की सभा

सुजड़ौला (राजस्थान) : 30 अगस्त को यहां ऑल इण्डिया कृषक खेत मजदूर संगठन (एआईकेकेएम) की सभा हुई। सभा के मुख्य वक्ता एसयूसीआई(सी) के हरियाणा राज्य कमेटी सदस्य कॉ. रामफल थे। सभा की अध्यक्षता कॉ सुभाष ने की और संचालन कॉ. राजेन्द्र सिहाग ने किया। सभा में पिलानी से भवानी सिंह व बीर सिंह और सुजड़ौला के बहुत सारे किसान और खेतमजदूर शामिल हुए। सभा में कृषि भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाने, किसानों को सभी फसलों के लाभकारी दाम देने, फसल खराबे का उचित मुआवजा देने, बिजली-पानी पूरा देने, खेत मजदूरों को सारे साल काम देने और सामाजिक सुरक्षा देने, कृषि सब्सिडी बढ़ा कर खाद, बीज, कीटनाशक, औजार व डीजल आधे दामों पर देने, ब्याजमुक्त कर्ज देने आदि मांगों को लेकर आन्दोलन तेज करने का आह्वान किया गया।

सभा में संगठन की 7 सदस्यीय गांव कमेटी गठित की गई जिसके अध्यक्ष हरि सिंह श्योराण, सचिव महावीर श्योराण के अलावा कन्हीराम, महेन्द्र सिंह, रामकिशन श्योराण, नरेश कुमार सिरोबा, किसनाराम और ईश्वर सिंह शामिल थे।

पेयजल की समस्या को लेकर सौंपा ज्ञापन

निमोठ (हरियाणा) : गांव में पेयजल की समस्या को लेकर 4 अगस्त को ऑल इण्डिया कृषक खेतमजदूर संगठन के संगठक कॉ. रामकुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने कार्यकारी अभियंता जल आपूर्ति कोसली को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि गांव में नियमित रूप से पानी की सप्लाई दी जाए, जहां पाइप लाइन नहीं वहां यह बिछाई जाए और ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले ऑपरेटरों का तबादला किया जाए। ज्ञापन देने वालों में नम्बरदार सुरेश, सुमेर सिंह, जगदीश, रामचंद्र, सरजीत, थावर सिंह व नरेश कुमार शामिल थे।

सड़कों पर उतरी आशा कार्यकर्ता

रिवाड़ी : एआईयूटीयूसी से सम्बद्ध आशा कार्यकर्ता यूनियन के तत्वावधान में 25 अगस्त को यहां सैकड़ों आशा वर्करों ने समस्याओं को हल न किये जाने पर राव तुलाराम पार्क से लेकर सचिवालय तक जोरदार विक्षोभ प्रदर्शन कर उपायुक्त, रिवाड़ी की मार्फत मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई की आशा वर्करों को 15000 रुपये प्रति माह मेहनताना दिया जाए, सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए, आशा वर्करों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। प्रदर्शन को मंजू, तारा देवी, उर्मिला, कृष्णा, संतोष, बिमला समेत अनेक आशा कार्यकर्ताओं ने सम्बोधित किया।

आशा कार्यकर्ता यूनियन के प्रांतीय सलाहकार कॉ. राजेन्द्र सिंह एडवोकेट ने प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित किया। उन्होंने अपने सम्बोधन में कहा कि आशा वर्करों के लम्बे संघर्ष के बाद पूर्ववर्ती सरकार ने उनको मिलने वाले मानदेय में 500 रुपये प्रति माह की और आइटमवाइज भी कुछ बढ़ोतरी की थी लेकिन भाजपा सरकार ने वह भी छीन ली। यह सरकार का घोर जनविरोधी कदम है। जबकि आशा वर्कर सरकार की स्वास्थ्य नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर अपनी भूमिका निभाती हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने आशा वर्करों की जायज मांगों को पूरा नहीं किया तो आन्दोलन और ऊंचे स्तर पर जा सकता है। ऑल इण्डिया यूटीयूसी के स्थानीय नेता बलराम यादव, कृषक खेतमजदूरों के नेता रामकुमार भी बात रखी।

कॉ. कृष्ण चक्रवर्ती का भाषण ..!!

(पृष्ठ 4 का शेष)

कौन सी हैं? सर्वहारा –ग्रामीण सर्वहारा (खेतिहर मजदूर) और शहरी सर्वहारा(औद्योगिक मजदूर) इन्हें संगठित करना होगा और अर्धसर्वहारा तबका मसलन गांव के लोग जो छोटी जोत के मालिक हैं जिन पर खेती करके वे अपने परिवारों का भरण-पोषण नहीं कर सकते–बाकी समय में वे दूसरे के खेतों में काम करते हैं, उनका किसान और उजरती गुलाम का चरित्र है, इसीलिए इन्हें अर्धसर्वहारा जनता कहा जाता है। हमारे देश में ये बड़े तबके हैं। इसी तरह शहरी स्थानों में भी मोची, बढ़ई, बुनकर जैसे मजदूर वे चीजें पैदा करते हैं और बेचते भी हैं लेकिन वे खुद मजदूर हैं, ऐसे लोगों को संगठित करना है और सर्वहारा तथा जनता के अर्धसर्वहारा तबके के बीच एकता कायम करनी है। मध्यम वर्ग है जिसे क्रान्ति के पक्ष में खींच लाना होगा या हितैषी तटस्थ बनाना होगा तभी पूँजीपति वर्ग अलग-थलग होगा और क्रान्ति के लिए स्थिति पैदा होगी। इससे पहले हथियार उठाना दुस्साहस होगा। नक्सलयों ने इसे कतई नहीं समझा, उन्होंने लोगों को तैयार नहीं किया लेकिन उन्होंने हथियार उठा लिये। यही वजह है कि लोग सोचते हैं कि क्रान्ति का मतलब है खून-खराबा, व्यक्तिगत हतयाएं। इस बात को हमें साफ तौर पर समझना होगा।

सीपीआई(एम) की गलत लाइन

अब सीपीआई(एम) की लाइन क्या है? सीपीआई(एम) का पूरा विश्लेषण हास्यास्पद घोलमट्ठा है; वे नहीं स्वीकारेंगे कि भारत एक पूँजीवादी देश है। वे कहते हैं कि भारत अभी भी एक उपनिवेश है। तब कैसी राजसत्ता है भारत? आज सिर्फ दो तरह की राजसत्ताएं हो सकती हैं–पूँजीवादी राष्ट्रीय राजसत्ताएं, जैसे अमेरिका, इंग्लैण्ड, बांग्लादेश इत्यादि में हैं और दूसरी समाजवादी राजसत्ताएं, जैसे उत्तरी कोरिया, क्यूबा (क्यूबा की बुनियाद भी बहुत बुरी है, कब यह ढह जाएगी, हम नहीं जानते, हमें इसके लिए इंतजार करना होगा, हालाँकि बहुत कष्टदायक है) इसलिए दो तरह के ही देश हो सकते हैं–पूँजीवादी देश और समाजवादी देश। बीच में और कुछ नहीं हो सकता है। सीपीआई(एम) कभी नहीं स्वीकारती है कि भारत एक पूँजीवादी देश है; निश्चित ही वे यह भी नहीं कहेंगे कि भारत एक समाजवादी देश है। तब सीपीआई(एम) के अनुसार भारत किस तरह का देश है? देखिये भारतीय राजसत्ता का चरित्र निर्धारण करते समय वे किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं–भारत एक बुर्जुआ लैण्डलोर्ड स्टेट है जिसके नेतृत्व में बड़े पूँजीपति हैं। यह वर्ग सहयोग के सिवा और कुछ नहीं है। न तो इस तरह की कोई राजसत्ता है, न ही कोई देश है पूरी दुनिया में। मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन, माओ की शिक्षाओं के आधार पर कॉमरेड शिवदास घोष ने कहा था कि कि अगर तर्क की खातिर यह मान भी लिया जाए कि भारत एक बुर्जुआ लैण्डलोर्ड स्टेट है जिसके नेतृत्व में बड़े पूँजीपति हैं तब भी प्रधान चरित्र पूँजीपति वर्ग है, राजसत्ता जिसके नेतृत्व में बड़े पूँजीपति हैं का मतलब है यह एक पूँजीवादी राजसत्ता है, सीपीआई(एम) इसे स्वीकार करे। यह वे स्वीकार नहीं करेंगे। निरूपण के अनुसार वे कहते हैं कि वे जनगणतांत्रिक क्रान्ति करेंगे जैसी कि चीन, वियतनाम, कम्बोडिया, उत्तरी कोरिया और क्यूबा में हुई थी। इनमें क्रान्तिकारी वर्ग कौन था? इन देशों में क्रान्तिकारी सर्वहारा वर्ग अर्धसर्वहारा जनता और राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग के साथ मिल कर विदेशी हमले के खिलाफ लड़ा था। जब भारत में सीपीआई(एम) राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग को न केवल प्रगतिशील के रूप में चित्रित करती है बल्कि क्रान्ति का दोस्त बताती है तब हम किस के खिलाफ लड़ रहे हैं? टाटा, बिड़ला, गोयन्का या कुछ व्यक्तियों के खिलाफ क्या ऐसा है? वे पूँजीवाद का साधारण नियम भी नहीं समझते हैं जहाँ बड़े पूँजीपति हैं, वहाँ छोटे पूँजीपति भी हैं। छोटे पूँजीपतियों को वे राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग के रूप में चित्रित करते हैं। पूँजीवाद में छोटा पूँजीपति बड़े पूँजीपति के खिलाफ क्यों लड़ेगा? क्योंकि बड़ा पूँजीपति छोटे पूँजीपति को बड़ा नहीं बनने दे रहा है। यह उनका संघर्ष है बड़ा बनने के लिए छोटे पूँजीपति का संघर्ष। अगर समाजवाद आता है तो छोटी पूँजी भी जायेगी, तब वे क्रान्ति का समर्थन क्यों करेंगे? यह साधारण सी बात सीपीआई(एम) नहीं समझती है। इसलिए उनकी क्रान्ति की लाइन एक बहुत बड़ी गुत्थी है, घालमेल है, बिल्कुल अस्पष्ट है। शायद यही वजह है कि वे बड़े पूँजीपतियों(बीजेपी) के खिलाफ कांग्रेस (राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग) के साथ गठजोड़ करते हैं! असल में बड़े पूँजीपति कांग्रेस की भी मदद करते हैं और बीजेपी की भी। असल में बड़े पूँजीपति आजादी पूर्व के समय से ही कांग्रेस की मदद करते आ रहे हैं। इन्होंने क्रान्ति के दुश्मन को ही क्रान्ति का दोस्त बना लिया है। इस प्रकार वे मजदूर वर्ग को भ्रमित कर रहे हैं। यही वजह है कि चुनावों के दौरान वे कांग्रेस से हाथ मिलाते हैं और इसको स्वीकार न कर पाने की वजह से उनकी पार्टी में कॉमरेडों का एक तबका सवाल उठाता है कि हम क्यों राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग के साथ हाथ मिलायें, हमें फौरन क्रान्ति शुरू कर देनी चाहिए। इस सवाल पर पार्टी नेतृत्व से मतभेद के चलते यह तबका पार्टी से बाहर निकल आता है और तब दुस्साहस शुरू होता है। इस तरह अविभाजित सीपीआई टूट कर सीपीआई और सीपीआई(एम) में बंट गई, फिर सीपीआई(एम) ने कांग्रेस के साथ हाथ मिला कर चुनाव लड़ना शुरू किया और तब सीपीआई(एमएल) बाहर आ गई। या तो वे दक्षिणपंथी अवसरवाद की तरफ या वाम दुस्साहसवाद की तरफ झुकते हैं। वे नहीं समझते हैं कि इन दोनों लाइनों में से किसी भी लाइन का क्रान्ति करने से कोई सम्बंध नही है। सीपीआई और सीपीआई(एम) के बीच अन्तर यह है कि सीपीआई(एम) कहती है जो संयुक्त मोर्चा क्रान्ति को अंजाम देगा उसका नेतृत्व सर्वहारा वर्ग करेगा और इसीलिए यह जनगणतांत्रिक क्रान्ति है, जबकि सीपीआई भी वही बात करती है, उसका भी वही विश्लेषण है सिवाय इसके कि सर्वहारा वर्ग राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग के साथ मिल कर क्रान्ति को अंजाम देगा, इसलिए यह राष्ट्रीय जनवादी क्रान्ति है। सीपीआई (एमएल) भारत को एक स्वतंत्र देश ही नहीं मानती है। फिर भी चाहे वे कितने ही गलत हों, कम से कम अपने सिद्धांत पर निरंतर कायम हैं। वे कहते हैं कि भारत एक अर्धसामंती, अर्ध-औपनिवेशिक देश है इसलिए जनगणतांत्रिक क्रान्ति सामान्य, तार्किक और स्वाभाविक है। लेकिन ये सभी भारत की वास्तविकता से कोसों दूर हैं। भारत पूरी तरह से एक पूँजीवादी देश है इसलिए यहाँ पूँजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रान्ति होगी। इसे हमें गहराई से समझना चाहिए और इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए जीवन के तमाम पहलुओं को समेटे हुए चौतरफा संघर्ष छेड़ने की जरूरत है। इसी वजह से कॉमरेड शिवदास घोष ने जीवन के तमाम पहलुओं को समेटे हुए क्रान्ति और क्रान्तिकारी आन्दोलन की समग्र समझदारी दी कि एक क्रान्तिकारी को कैसा होना चाहिए इसका सम्पूर्ण विचार उन्होंने दिया। सीपीआई-सीपीआई(एम) पार्टी में वे राष्ट्रीय जनवादी क्रान्ति (एनडीआर), जनगणतांत्रिक क्रान्ति (पीडीआर) आदि हर चीज को भ्रमित करते हैं। वे सांस्कृतिक सवालों को चर्चा के लिए नहीं उठाते हैं। उनमें एक क्रान्तिकारी की असल धारणा ही नहीं है। उनका साहित्य पढ़िये, उसमें आप इन पहलुओं पर कुछ भी नहीं पायेंगे। इसलिए वे क्रान्ति को संगठित नहीं कर सकते हैं। क्रान्ति हर किसी व्यक्ति द्वारा संगठित नहीं की जा सकती, क्रान्तिकारियों द्वारा ही क्रान्ति की जा सकती है। ये क्रान्तिकारी कौन हैं यह हमें समझना चाहिए।

एसयूसीआई(सी) और खुद को वामपंथी बताने वाली पार्टियों के बीच फर्क

क्रान्ति की हमारी लाइन के साथ इन तथाकथित वामपंथी पार्टियों के बुनियादी फर्क को हमें समझना चाहिए। उन्होंने भयंकर भ्रान्ति पैदा कर दी है और कर रहे हैं। वे बड़ी पार्टियाँ हैं। एक समय उनका समर्थन स्टालिन, माओ त्से-तुंग जैसे अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने किया था जहाँ कहीं भी नये देशों में कम्युनिस्ट पार्टियाँ पनपी, उन्होंने उनको मान्यता दे दी। जैसा कि कॉमरेड शिवदास घोष ने सही ढंग से दिखाया कि वे कम्युनिस्ट हैं भी या नहीं इसकी जाँच तो उस देश के सर्वहारा वर्ग द्वारा की जायेगी। उनके पूरे आचरण से अब यह बिल्कुल साफ है, लोग विक्षुब्ध हैं, कम्युनिज्म के नाम से ही वे खार खाते हैं, विरोध करते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संशोधनवादी ख्रुश्चेव या संशोधनवादी तेंग श्याओ पिंग ने समाजवाद को ध्वस्त कर दिया तब एक तरफ सीपीआई, सीपीआई(एम) के दक्षिणपंथी अवसरवाद और दूसरी तरफ नक्सलवादियों के वामपंथी दुस्साहसवाद के मुकाबले हमें लोगों को संघर्ष की सही लाइन दिखानी पड़ी। तथ्य यह है कि हम संघर्ष की सही लाइन और जीवन की उच्च धारणा, नीति-नैतिकता के सवालों पर स्पष्टता को दर्शा रहे हैं, इस लिए लोग हमारी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। क्या वे हमारी राजनैतिक लाइन जो मैंने अभी आपके सामने रखी, उसे समझते हैं? क्या वे हमारे और सीपीआई, सीपीआई(एम), सीपीआई(एमएल) के बीच फर्क को समझते हैं? क्या पूँजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रान्ति और राष्ट्रीय जनवादी क्रान्ति व जनगणतांत्रिक क्रान्ति के बीच बुनियादी फर्क को वे समझते हैं? वे इतनी आसानी से इसे नहीं समझ सकते, हमें उन्हें समझाना होगा लेकिन वे हमारी तरफ आकर्षित हैं। तथ्य यह है कि हमारी पार्टी बढ़ रही है। क्यों और कैसे? क्योंकि वे देखते हैं कि हमारे नेता-कार्यकर्ताओं की संस्कृति, उनका ज्ञान, उनकी लगन, उनका कुर्बानी का जज्बा, क्रान्ति के प्रति उनका पूर्ण समर्पण, उनकी निष्ठा, उनकी ईमानदारी, ये चीजें उन्हें आकर्षित करती हैं। जब वे आकर्षित हो जाते हैं तो हम उनके समझने लायक तरीके से क्रान्ति की अवधारणा को समझाते हैं। क्रान्ति की अवधारणा उन्हें समझाये बिना वे क्रान्ति के पाले में नहीं आ सकते। अगर वे समझ नहीं पाये कि पूँजीवाद क्या है, साम्राज्यवाद क्या है, क्यों यह मरणासन्न और प्रतिक्रियावादी हो गया है तो वे इसके खिलाफ क्यों लड़ेंगे? अगर लोग यह न समझें कि समाजवाद क्या है और कैसे समाजवाद बुनियादी तौर पर पूँजीवादी समाज से भिन्न है, क्यों समाजवाद में जीवन की समस्याओं का समाधान होगा और कैसे समाज समाजवाद की तरफ प्रगति करेगा, जब तक वे इन बातों को नहीं समझ जाते और कौन सी पार्टी इसे हासिल कर सकती है, जब तक वे उस पार्टी को पहचान नहीं लेते तब तक क्रान्ति कैसे हो सकती है? इसलिए कॉमरेडों को इन सब को गहराई से समझना होगा। जो कुछ मैंने यहाँ रखा वह सभी पार्टी साहित्य में है लेकिन स्थिति आज इन सभी को दोहराने, इसे याद करने, कॉमरेड शिवदास घोष के विचारों को मेहनत से बार-बार पनपाने की माँग करती है। क्योंकि ये बातें हमें लोगों तक ले जानी होंगी। हमारे बारे में कौन बतायेगा? अखबार क्या हमारी राजनैतिक लाइन को छापेंगे? क्या पूँजीपति वर्ग हमारे बारे में प्रचार करेगा? कॉमरेड शिवदास घोष कहा करते थे कि क्रान्तिकारियों को अपना ढोल खुद ही बजाना होगा, हम चिल्ला कर अपने विचारों को फैला रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं है–जिसे हम कहते हैं कानाफूसी अभियान–जो हमसे सहमत हुए हैं वे हमारे बारे में अपने दोस्तों, परिजनों और पड़ोसियों से बतायें और वे फिर इसी तरह आगे बतायें, इस तरह हमारे विचार फैलते जायें। जब हम अपने दोस्तों, परिजनों और पड़ासियों के जरिये लाखों लोगों तक पहुँचेंगे तो सारा देश कॉमरेड शिवदास घोष के विचारों से परिचित हो जायेगा। इसलिए कॉमरेडों आज संघर्ष यही है।

क्रान्ति और समाजवाद के बारे में भ्रान्तियों और गलतफहमियों को हमें दूर करना होगा

लेकिनें क्रान्ति के विचार को लोगों तक ले जान से पहले हमें लोगों की मानसिकता को समझना होगा। हमसे जो लोग सहमत हुए हैं उनमें भी साम्यवाद के बारे में ही भ्रान्तियाँ हैं। इस पर भी मैं कुछ बात रखना चाहूँगा। इसमें कुछ समय लग सकता है लेकिन ध्यान से सुनिये। पहले तो लोग कहते हैं कि समाजवाद रूस में, चीन में, सभी जगह ध्वस्त हो गया है तब आप क्यों अब समाजवाद के लिए लड़ रहे हो? समाजवाद टिक नहीं सकता जबकि पूँजीवाद स्थिर है, यह रहेगा, यह आखिर तक रहेगा, सैकड़ों साल से यह अनवरत है। ठीक है पूँजीवाद में कुछ कमियाँ हैं, गलतियाँ हैं, अपर्याप्तताएं हैं इन्हें हमें दुरुस्त करना होगा, सुधारना होगा लेकिन पूँजीवाद अंतिम बात है। समाजवाद समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है। इसका जवाब क्या है? संक्षेप में, अब मैं यह बता रहा हूँ। अगर जरूरत पड़े तो बाद में आप अपने नेताओं से विस्तार से चर्चा कर लें। समाजवाद क्रान्ति की अंतिम बात नहीं है, यह क्रान्ति का एक स्तर है। पूँजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच संघर्ष लगातार जारी है। पूँजीवादी समाज में पूँजीपति वर्ग है जो शासन

(शेष पृष्ठ 7 पर)

कॉ. कृष्ण चक्रवर्ती का भाषण ..!!

(पृष्ठ 6 का शेष)

करता है और मजदूर वर्ग शोषित-पीड़ित व शासित होता है। पूँजीपति वर्ग को सत्ता से उखाड़ फेंक कर मजदूर वर्ग सत्ता में आता है और एक सर्वहारा क्रान्तिकारी राजसत्ता कायम करता है। मजदूर वर्ग जब सत्ता में होता है तब भी पूँजीपति वर्ग निर्मूल नहीं हो जाता है, खत्म नहीं हो जाता है, परास्त हो जाने के बावजूद, समाजवादी समाज में भी पूँजीपति वर्ग बरकरार रहता है लेकिन यह सत्ता में नहीं होता। लेनिन ने दिखाया कि समाजवादी देशों में पराजित पूँजीपति वर्ग का अंतर्राष्ट्रीय पूँजीपतियों और प्रतिक्रियावादियों से काफी सम्बंध रहता है। यह परिस्थिति पूँजीपतियों को उससे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर बना देती है जब वे सत्ता में थे। वे इस परिवर्तन को पलट देने के लिए, प्रतिक्रान्ति कर देने के लिए और सत्ता वापस हथियाने की न केवल कोशिश करते हैं बल्कि असल में कदम भी उठाते हैं। इसलिए मजदूर वर्ग अगर चौकस न रहे, अगर मजदूर वर्ग के सांस्कृतिक स्तर, चिंतन के स्तर को निरंतर ऊंचा न उठाया जाए, विकसित न किया जाए तो असावधानी की अवस्था में पूँजीपति वर्ग पलट वार करेगा और मजदूर वर्ग को सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। यही कुछ समाजवादी देशों में हुआ। जब तक स्टालिन जिन्दा थे, माओ जिन्दा थे, तब तक पूँजीपति वर्ग उलटाव नहीं ला सका, ये महान क्रान्तिकारी नेता इस तथ्य को जानते थे कि अगर लोग चौकस न रहे, सिर पर मंडराते खतरे से अनभिज्ञ रहें, उनका सांस्कृतिक स्तर पर्याप्त न रहे और उनका वैचारिक स्तर ऊंचा न उठे तो पूँजीपति वर्ग सत्ता में वापस आ सकता है। जब स्टालिन का देहांत हुआ तो ख्रुश्चेव और उसके गैंग ने सत्ता हथिया ली, छिपा हुआ पूँजीपति वर्ग और वर्गद्रोही धीरे-धीरे सत्ता में आ गये और प्रक्रिया पलट दी। यह पूरी तरह प्रतिक्रान्ति करने में 30-35 साल लगे।

अगर सही मार्क्सवादी प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया तो प्रतिक्रान्ति हो जाने के बार में सभी मार्क्सवादी ॲथोरिटियों ने चेतावनी दी थी।

इसलिए, जब तक पूँजीपति वर्ग बरकरार है मजदूर वर्ग के सत्ता में रहते हुए भी संघर्ष जारी रहता है। कभी-कभी अगर मजदूर वर्ग की तरफ से यह संघर्ष कमजोर पड़ता है तब प्रतिक्रान्ति हो सकती है। लेनिन, स्टालिन, माओ ने यह बताया और रूस में जब ख्रुश्चेव सत्ता में आया तब इसे रोकने के लिए इसके खिलाफ संघर्ष छेड़ने के लिए कॉमरेड शिवदास घोष ने अनेक बार चेतावनी दी थी लेकिन ऐसा न हो पाया। लेकिन जब क्रान्ति को पूरी तरह सरअंजाम दे दिया जायेगा, जब वर्गों का खात्मा हो जायेगा-पूँजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग दोनों का ही खात्मा हो जायेगा, उस स्तर पर प्रतिक्रान्ति फिर नहीं हो सकेगी। लेकिन समाजवाद में, जो एक संक्रमणकालीन दौर है इसमें अगर समाजवादी लाइन का अनुसरण किया जाए, समाजवादी संस्कृति से लैस किया जाए तो अग्रगति हो सकती है और धीरे-धीरे विकास करते-करते साम्यवाद में जाना भी सम्भव है। अगर इसमें कमी रहे तो उलटाव की सम्भावना भी बराबर बनी रहती है। सभी क्रान्तियों में आगे बढ़ना और पीछे हटना है, जीत और हार है, इसलिए रूस या चीन में एक जीत या हार से संघर्ष का अंत नहीं हो जाता है। यह अंतिम बात नहीं है जो हुई है। मजदूर वर्ग मौजूद है। शोषणमूलक पूँजीवादी राजसत्ता मर रही है। इसके जीवन की घड़ियाँ और नहीं बची हैं; किसी तरह वेन्टिलेटर पर बाहर से आक्सीजन पाकर यह जिन्दा है। लेकिन अगर मजदूर संगठित हो जाएं, तो पूरी दुनिया में सभी देशों में पूँजीवाद को उखाड़ फेंक दिया जायेगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रतिक्रान्ति के बारे में भ्रमित होने की कोई बात नहीं है, फिर भी रूस और चीन दोनों में प्रतिक्रान्ति की सम्भावना थी। लेनिन ने बताया,''समाजवाद का मतलब वर्गों का खात्मा है।'' लेकिन वर्गों का खात्मा नहीं हो सका। वर्ग हैं सिर्फ उनकी भूमिका परस्पर बदल गई। पूँजीपति वर्ग को सत्ता से उखाड़ फेंका गया लेकिन खात्मा नहीं हुआ। ऐसी एक परिस्थिति में, वे वापस आ सकते हैं और आ भी गये। इस वजह से परेशान होने की कोई बात नहीं है। संघर्ष पुनः जारी रहेगा, उसी रूस में क्रान्ति के साथ समाजवाद फिर दोबारा लौट कर आयेगा। पूँजीवाद जीवन की समस्याओं को हल नहीं कर सकता है।

क्रान्ति कभी अपने आप नहीं हो जाती है

लेकिन यहाँ एक और सवाल को समझना होगा। वह यह कि तब क्या संकट ही क्रान्ति पैदा करता है? संकट दमन-उत्पीड़न को बढ़ायेगा इसी से क्रान्ति नहीं हो जायेगी। नक्सलवादी यकीन करते हैं कि जहाँ दमन होता है, वहाँ बगावत फूट पड़ती है। जहाँ कहीं भी संकट है, वहाँ क्रान्ति के लिए लोग आगे आयेंगे। ऐसा कदापि नहीं होता। मार्क्स-एंगेल्स-लेनिन-स्टालिन-माओ सभी ने दिखाया कि सिर्फ संकट के चलते ही क्रान्ति नहीं हो जायेगी। इथोपिया में भयंकर संकट और भुखमरी की वजह से लोग हड्डियों का ढाँचा मात्र बन गये हैं, लेकिन वहाँ क्रान्ति तो नहीं फूट पड़ी। इसकी बजाय लोगों ने भीख माँगना शुरू कर दिया, जब तक सचेत संगठित सर्वहारा नहीं हो तब तक क्रान्ति नहीं हो सकती है। इसे आप याद रखिये और यकीन कीजिए। इसलिए, यह जवाब उनको देना होगा जो सवाल करते हैं कि समाजवाद लाने के लिए हमें क्यों लड़ना चाहिए और उनको आश्वस्त करना होगा कि क्रान्ति पुनः वापस आयेगी, यह निश्चित ही आयेगी। अगर हम इसे अंजाम नहीं दे सके तो हम बेकार, निष्फल सिद्ध हो जायेंगे। लेकिन कोई दूसरा आयेगा, वे संघर्ष करेगे और क्रान्ति करेंगे क्योंकि यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्रान्ति एक सामाजिक शक्ति है। यह तब होती है जब सचेत सर्वहारा बढ़ता है, जब वे खुद को संगठित कर लेते हैं।

समाजवाद ऊंचे दर्जे का लोकतंत्र प्रदान करता है

एक और बड़ी भ्रान्ति पूँजीवादी प्रचार के जरिये शिक्षितों, बुद्धिजीवियों-प्राध्यापकों, प्रोफेसरों, डाक्टरों, इंजीनियरों और ऐसे ही अन्य लोगों के बीच पैदा की गई है। आप उनके पास जाइये और समाजवाद के बारे में बताइये, जो कुछ भी आप कहें वे जवाब में कहेंगे कि समाजवाद में कोई लोकतंत्र नहीं है। ऐसा लगता है मानो उनके दिमागों में यह ठूंस दिया गया है कि समाजवाद में लोकतंत्र नहीं है। वे सोचते हैं कि लोकतंत्र तो लोकतांत्रिक देशों-राष्ट्रीय पूँजीवादी देशों में ही हो सकता है। इस बड़ी भ्रान्ति की वजह से समाजवाद के प्रति एक प्रतिरोध आ गया है। इसलिए, इस बिन्दु को भी हमें गहराई से समझना होगा। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र व्यक्तिगत आजादी पर आधारित है और खास तौर पर बराबरी पर आधारित है। बराबरी लोकतंत्र का आधार है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक-सभी क्षेत्रों में बराबरी। पूँजीपति वर्ग ने ही बराबरी, स्वतंत्रता और भाईचारे के नारों को सामंतवाद के खिलाफ उठाया था। उन दिनों यह महान था क्योंकि व्यक्तियों की कोई स्वतंत्रता नहीं थी। सामंती भू-स्वामी निरंकुश शासन, राजतंत्र का तानाशाही शासन चलाते थे और प्रजा की विशाल जनता दमन-उत्पीड़न की शिकार थी -इन हालात में समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे का नारा एक महान नारा था। लेकिन अंततः क्या पूँजीपति वर्ग समानता दे पाया? क्या पूँजीवादी व्यवस्था में कोई समानता हो सकती है? क्या निजी सम्पत्ति की गारण्टी देने वाली एक पूँजीवादी व्यवस्था में समानता हो सकती है जिस निजी सम्पत्ति को पवित्र अधिकार के रूप में राजसत्ता की स्वीकृति है? क्या पूरा समाज, समाज के सभी लोग उत्पादन के साधनों के मालिक हो सकते हैं? नहीं, केवल चंद लोग ही उत्पादन के साधनों के मालिक हो सकते हैं जैसे टाटा, बिड़ला, गोयन्का, अम्बानी, अडानी इत्यादी। ये लोग फैक्टरियों, उद्योगों, बड़-बड़े फार्मों के मालिक हैं। तथ्य यह है कि महनतकश लोग उनमें नौकरी करते हैं, रोजगार करते हैं। इस रोजगार का मायने क्या हैं? लोग वहाँ पूँजीपति मालिकों को अपनी श्रम शक्ति बेचते हैं। सुनने में चाहे कितना ही कठोर लगे, पर सच यह है कि पूँजीपति मजदूर वर्ग की श्रम शक्ति को खरीदते हैं। मजदूर वर्ग रोजगार के लिए उनके उद्योगों में, फैक्टरियों में श्रम शक्ति को बेचता है। श्रम शक्ति को जो खरीदते हैं और श्रम शक्ति को जो बेचते हैं क्या वे बराबर हो सकते हैं? अज्ञानियों या पूँजीपतियों से अभिप्रेरित एजेण्टों के सिवा कौन सोच सकता है कि श्रम शक्ति को बेचने वालों और श्रम शक्ति को खरीदने वालों के बीच समानता हो सकती है? लेनिन ने इसे उजरती गुलामी की संज्ञा दी थी। आज आप देखते हैं कि मौजूदा व्यवस्था में बराबरी के नारे का क्या हश्र हुआ।

एक तरफ समाजवाद में कोई निजी सम्पत्ति नहीं होगी। हालांकि निजी सम्पत्ति के उन्मूलन में कुछ समय लगेगा लेकिन धीरे-धीरे इसका उन्मूलन कर दिया जायेगा। जैसे भी उत्पादन के तमाम साधनों-फैक्टरियों, मिलों, कारखानों, बड़े फार्मों का मालिकाना पूरे सर्वहारा वर्ग द्वारा नियंत्रित किया जायेगा, किसी व्यक्ति -लेनिन, स्टालिन, माओ द्वारा नहीं। यह वर्ग का एकनायकत्व है; यह उत्पादन के साधनों पर सामाजिक मालिकाना कायम करेगा। समाजवादी समाज में सख्त नियम होगा कि आप मजदूर भाड़े पर नहीं रख सकते हैं। वहाँ लेबर मार्केट नहीं है। श्रम शक्ति को खरीदा नहीं जा सकता। इसलिए मजदूर ही उत्पादन के साधनों के मालिक हैं और मजदूर ही खुद काम करने वाले वर्कर हैं। पूँजीवाद की तरह मालिक और जिन पर मालिकाना हो कोई फर्क नहीं है। दूसरे, पूँजीवाद में उत्पादन मुनाफे को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए होता है। जिसे मजदूरों का शोषण करके उनके द्वारा पैदा किये सरप्लस को हड़प कर ही कमाया जा सकता है। समाजवाद में व्यक्तिगत मुनाफे का सवाल ही नहीं उठता है; उसमें उत्पादन, उच्च उत्पादन समाज की बढ़ती जरूरतों को पूरी करने के लिए होता है; उत्पादन में सामाजिक-सांस्कृतिक पहलू भी शामिल हैं। जरूरत उत्पादन को तय करती है, समाजवादी उत्पादन का यही उद्देश्य है। समानता केवल वहीं हासिल की जा सकती है जहाँ उत्पादन के साधनों पर निजी मालिकाना नहीं है, जहाँ पूरा समाज ही उत्पादन के साधनों का मालिक है। फिर भी समाजवाद में कुछ निजी सम्पत्ति रहेगी खुद का बाग-बगीचा, ऐसी चीजें कुछ समय के लिए रहेंगी लेकिन अंततः ये भी चली जायेंगी। सब कुछ सामाजिक होगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि साम्यवाद में जाने का एक संघर्ष है समाजवाद। जब सारी सम्पत्ति सामाजिक सम्पत्ति है; तभी सही मायने में समानता हासिल की जा सकती है। जिसे लोकतंत्र कहते हैं. इतिहास में लोकतांत्रिक दौर पूँजीवादी समाज से शुरू हुआ था। सामंतवाद में समानता, व्यक्तिगत आजादी और स्वतंत्रता का सवाल ही नहीं था। समाजवाद के साथ यह खत्म होता है। यह समाज के लोकतांत्रिक काल का दौर है। पहले को बुर्जुआ लोकतंत्र के रूप में जाना जाता हैऔर दूसरे को सर्वहारा लोकतंत्र के रूप में। जब यह सवाल आया तो लेनिन ने दिखाया कि पूँजीवाद में कोई लोकतंत्र नहीं है जबकि समाजवाद में सच्चा लोकतंत्र है। वहाँ 90 प्रतिशत मजदूर वर्ग के खिलाफ 10 प्रतिशत मालिक वर्ग के लिए लोकतंत्र है। यह संकीर्ण है, लोकतंत्र का आयाम छोटा है जबकि समाजवाद में 90 प्रतिशत लोकतंत्र का सुख पाते हैं और 10 प्रतिशत पूँजीपतियों को सत्ता से उखाड़ फेंका है। इसलिए अगर हम आयाम को देखें तो समाजवाद में लोकतंत्र का विस्तार ज्यादा है। इससे भी महत्वपूर्ण है बुर्जुआ लोकतंत्र शोषण की रक्षा करता है, इसलिए संस्कृति पतित है जबकि समाजवाद में, समाजवादी लोकतंत्र आदमी को मुक्त करता है, उत्पादन को मुनाफा कमाने के उद्देश्य से मुक्त करता है। यह विशाल और महान लोकतंत्र है। इसलिए आकार में, सर्वहारा लोकतंत्र न केवल बड़ा है बल्कि गुणवत्ता में भी ऊंचे दर्जे का है। फिर जब हम साम्यवाद में प्रवेश कर जाते हैं; वर्गों का खात्मा हो जाता है, वर्ग का शासन चला जाता है, उत्पादन बहुतायत में पहुँच जाता है। कोई भी जो चाहे ले सकता है। प्रत्येक अपनी योग्यता के अनुसार, प्रत्येक अपनी जरूरत के अनुसार। यह होगा काम करने का सिद्धांत। इसलिए असल समानता साम्यवाद में आयेगी। लोकतंत्र का सवाल भी खुद-ब-खुद गायब हो जायेगा। व्यक्तिगत आजादी का कोई सवाल नहीं रहेगा, लोकतंत्र के लिए संर्घ का भी कोई सवाल नहीं रहेगा। ये तमाम सवाल अस्तित्वहीन हो जायेंगे। ऐसा एक महान संघर्ष है साम्यवाद कायम करने का संघर्ष। इसलिए यह हमें गहराई से समझना है और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को समाजवाद और अंततः साम्यवाद निर्माण करने के इस महान संघर्ष में शामिल कराना है। कॉमरेड शिवदास घोष ने भारत की ठोस परिस्थिति में मार्क्सवाद-लेनिनवाद को विशेषीकृत किया है, इसलिए उनके विचारों को गहराई से समझें, गहराई से आत्मसात करें। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ।

पूँजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रान्ति जिन्दाबाद!

भारत की सरजमीं पर सही कम्युनिस्ट पार्टी एसयूसीआई(सी) जिन्दाबाद!

सर्वहारा के महान नेता कॉमरेड शिवदास घोष लाल सलाम!

8 R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2015-2017
Posting at IPMBC on 7–8 and 22–23 Fortnightly , Date of Printing : 5 Sept, 2015

सर्वहारा दृष्टिकोण

7 सितम्बर, 2015

आशा वर्करों के आन्दोलन की शानदार जीत

दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर धरना व प्रदर्शन करती आशा वर्कर

दिल्ली में आशा वर्करों की 40 दिन लम्बी चली हड़ताल, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर 28 जून से 7 अगस्त तक 40 दिन लगातार धरना व प्रदर्शन, 3 दिन तक क्रमिक भूख हड़ताल व 7 अगस्त को 1000 आशा वर्करों की सामूहिक भूख हड़ताल के बाद आखिर दिल्ली सरकार को आशा वर्करों के आन्दोलन के सामने झुकना पड़ा। 7 अगस्त को जब 1000 आशा वर्कर भूख हड़ताल पर थी, शाम को 7 बजे धरना व भूख हड़ताल स्थल पर सरकार के प्रतिनिधियों ने आकर दिल्ली आशा वर्कर्स एसोसियेशन की 20 सूत्री मांगों में से अधिकांश को स्वीकार करने की घोषणा की। उन्होंने यूनियन की महासचिव ममता राव व अध्यक्ष एम चौरसिया को जूस पिला कर सभी की भूख हड़ताल समाप्त करवाई।

एआईयूटीयूसी से सम्बद्ध दिल्ली आशा वर्कर्स एसोसियेशन के बैनर तले हुई इस हड़ताल को 7 अगस्त को दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से सम्बन्धित संसदीय सचिव श्री राजेश गुप्ता, लेजिस्लेटिव ब्यूरो के डायरेक्टर डा. रतनेश गुप्ता व स्वास्थ्य मंत्री की सलाहकार डा. श्रीमती सुरभि सिंह ने धरना स्थल पर पहुंच कर घोषणा की कि सरकार कोर इन्सेन्टिव को दुगुना करेगी, जनरल इंसेन्टिव में 25 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक की वृद्धि करेगी, 200 रुपये प्रति माह फोटो कॉपी के लिए देगी और मोबाइल फोन सीयूजी कनेक्शन सभी आशा वर्करों को दिया जायेगा। इसके अलावा कुछ और मांगों पर भी सकारातमक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

एआईयूटीयूसी के सर्वभारतीय सचिवमंडल के सदस्य कॉ. आर के शर्मा, दिल्ली राज्य अध्यक्ष हरीश त्यागी, दिल्ली आशा वर्कर्स एसोसियेशन की सचिव ममता राव व अध्यक्ष एआईयूटीयूसी के दिल्ली राज्य सचिव एम चौरसिया ने सभी आशा वर्करों को तमाम प्रतिकूलताओं के बावजूद एकजुट जुझारू आन्दोलन चलाने के लिए बधायी दी और कहा कि यह जीत पूर्ण नहीं है फिर भी महत्वपूर्ण है।

2 सितम्बर की हड़ताल के दृश्य

ग्वालियर

करोड़ीमल कॉलेज दिल्ली

रिवाड़ी

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश निरस्त होने पर एआईकेकेएमएस का बयान

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की मौत पर खुशी का इजहार करते हुए ऑल इण्डिया कृषक खेत मजदूर संगठन (एआईकेकेएमएस) ने इसे संयुक्त किसान आन्दोलनों की जीत बताया है। संगठन ने किसान-खेतमजदूरों को सचेत करते हुए कहा कि वे किसी गफलत के शिकार न हों। यह मात्र एक अध्यादेश की समाप्ति है, भाजपा की मोदी सरकार के मन्सूबे ज्यों के त्यों हैं।

किसान संगठन की ओर से 1 सितम्बर को जारी बयान में कॉमरेड सत्यवान ने कहा कि वर्षों से घाटे की खेती से जूझ रहे किसानों को राहत प्रदान करने की बजाय एक पर एक तीन बार किसान-विरोधी अध्यादेश लाकर मोदी सरकार ने उनके गहरे जख्मों को बुरी तरह से कुरेद दिया था। अपने बचाव में देश भर के किसान, खास कर गरीब-मध्यम किसान, खेतमजदूर व भूमिहीन सब जाग उठे और जोरदार प्रतिवाद संगठित किये। विभिन्न संगठनों, राजनैतिक दलों और बुद्धिजीवियों ने भी खुद अपने अपने स्तर पर और साझे मोर्चे बना कर भी इन अध्यादेशों को समाप्त करने और कृषि भूमि के अधिग्रहण पर पूर्ण रोक लगाने की मांग की। एआईकेएमएस ने हर स्तर पर इस देशव्यापी संघर्ष में प्रभावशाली भूमिका निभाई।

पिछले 10 साल में बड़ी मात्रा में येन-केन-प्रकारेण कृषि भूमि को हड़पा गया था जिसके खिलाफ नन्दीग्राम जैसे यादगार ऐतिहासिक सफल संघर्ष हुए थे। वह भूमि अभी भी काफी सारी खाली पड़ी है जिसमें न तो कोई उद्योग लगा और न ही किसी विकास कार्य के लिए उपयोग की गई। इसे वापस किसानों के हाथ में देने के लिए मांग उठती रही है। रिलायंस कम्पनी के रद्द हुए सेज के लिए झज्जर व गुड़गांव जिलों की 10 हजार एकड़ भूमि को वापस किसानों को दिलाने के लिए हमारा संघर्ष जारी है। इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में जनहित की परिभाषा समेत अनेक प्रावधान घोर किसान-विरोधी हैं। उन्हें हटा कर खेती-किसानर के पक्ष में बदलाव लाने के लिए भी हम अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। हमारा यह आन्दोलन जारी रहेगा। अब उन बिन्दुओं को फोकस में लाया जायेगा जो किसान-खेतमजदूरों को खुदकुशी के लिए मजबूर करते हैं। जब तक उन कारणों को जड़ से समाप्त नहीं कर दिया जाता, किसान-खेतमजदूर-भूमिहीनों के इस साझे आन्दोलन को पहले से भी ज्यादा तगड़ा और व्यापक बनाने की भरपूर कोशिश रहेगी

किसान-खेतमजदूरों को हर तरह से चौकस रहना होगा। मोदी सरकार पीछे जरूर हटी है लेकिन देशी-विदेशी पूंजी के स्वार्थ में बांधे गये उसके मन्सूबे नई रणनीति के साथ नाना रूपाकार लेने से नहीं चूकेंगे। इसमें बीजेपी के साथ कांग्रेस समेत विभिन्न दलों के मिल जाने की पूरी-पूरी आशंका शायद मिथ्या न रहे। प्रदेश सरकारें किसानों को आजमाना चाहेंगी। बीजेपी शासित प्रदेश सरकारें इसमें अगुआई कर सकती हैं। इसलिए मामले को हल्के में न लिया जाए। किसान-खेतमजदूर सचेत रहें ; किसी भी खुशफहमी या गफलत के शिकार न हों।

पंचायत चुनावों में पढ़े-लिखे होने की शर्त नाजायज

रोहतक (हरियाणा) : एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) पार्टी के हरियाणा राज्य सचिव कॉमरेड सत्यवान ने 13 अगस्त को जारी एक प्रेस बयान में कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा अचानक 8वीं-10वीं पास की शर्त लगाकर अनपढ़ या कम पढ़े-लिखे लोगों, खास कर महिलाओं को पंचायत चुनावों में भागीदारी से वंचित किये जाने का एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) कड़ा विरोध करती है। उन्होंने इसे जनतंत्र-विरोधी एक असंवैधानिक फरमान बताया। उन्होंने इसे तुरंत प्रभाव से वापस लेने की मांग की। पहले ही पंचायत चुनावों को टालने और पंचायतों को प्रशासन के हाथों में सौंपने का भाजपा सरकार एक जनविरोधी कृत्य कर चुकी है। एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के नेता ने कहा कि प्रदेश की बहुत बड़ी आबादी आज भी अनपढ़ या कम पढ़ी-लिखी है जिसके लिए वर्तमान आर्थिक-सामाजिक स्थिति, खास कर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली दोषी है जो इन सरकारों द्वारा पोषित है। गरीबी और आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा आज भी बहुत सारे परिवारों की पंहुच से बाहर है। ऐसे में उम्मीदवार की पात्रता के लिए 8वीं और 10वीं पास होने की शर्त थोपना सरासर नाजायज है।

"Print-line
Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Balaji Offset Printers, 315/21, Shahzada Bagh, Daya Basti, Delhi and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005. Editor: Com. Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C)."

Email: sarvaharadrishtikon@gmail.com , sarvaharadrishtikon@yahoo.com फोन नं. : 011-25726631